

## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 58/20

वर्ष 2020

जीसीएमएस संख्या 2020/00124

बउनवानी:-जागृति महला एवं सहायता समूह दौनायचा, उ.मू.दुकानदार ग्राम पंचायत बिच्छीदोना  
भाग, तहसील मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर

बनाम

जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर. द्वारा अभियोग संख्या  
59/2015 एवं 87/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड  
ग्रेन एवं असेसियल आर्टिकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थित:-श्री अभय कुमार गुप्ता

वकील अपीलान्त

श्री धर्मचन्द अग्रवाल (प्रवर्तन अधिकारी)

पैरोकार रसद

—:निर्णय :-


दिनांक:- 02.02.2021

प्रस्तुत अपील अपीलान्त द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के अभियोग संख्या  
59/2015 एवं 87/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 जिसके द्वारा अपीलान्त का  
प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि  
अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा में दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पों. की  
तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया  
जाकर अपील के सन्दर्भ में बहस वकील अपीलान्त एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित  
आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य  
होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त ग्राम पंचायत बिच्छुदौना  
की 1/3 भाग का उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। तथा बिना किसी शिकायत के  
उपभोक्ताओ को नियमित राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है किन्तु राजनैतिक  
रंजिशवश ग्राम दौनायचा के उपभोक्ताओ द्वारा की गयी झूठी शिकायत के आधार पर जिला  
रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि  
जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना वस्तुस्थिति एवं सुनवायी का अवसर दिये व बिना जाँच कराये  
दिनांक 26.11.2016 को अपीलान्त की दुकान का प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलम्बित कर  
जरिये पत्रांक 18.12.2015 एवं 8.2.2016 को जारी कर दुकान की जाँच के आदेश प्रवर्तन  
निरीक्षक को दिये गये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.2.2016 को जाँच कर जाँच  
रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर आदेश जैर अपील से अपीलान्त का प्राधिकार पत्र विधि विरुद्ध तरीके  
से निरस्त किया गया है। इससे पूर्व अपीलान्त का प्राधिकार पत्र जाँच विचाराधीन रखते हुए  
आदेश क्रमांक 221 दिनांक 11.3.2016 से बहाल कर दिया गया था। इस प्रकार अभियोग संख्या  
59/2015 को निस्तारण होने के उपरान्त पुनः आदेश क्रमांक /अभि./3782-3791 दिनांक 31.  
10.17 से प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए दिनांक 7.11.2017 को निरस्त करना विधि विरुद्ध  
है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त की सुनवायी हेतु जारी नोटिस दिनांक 21.4.2016, 21.4.17,  
31.5.2017, 28.6.2017, 14.7.2017, 22.8.2017, 12.9.2017, 20.9.2017, 30.10.2017 में से दिनांक  
22.8.2017 के नोटिस की तामील अपीलान्त को हुई थी

.....(1).....

  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

जिसमे आगामी तारीख 7.9.2017 नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे तारीख पेशी 10.5.2016 से 27.5.2017 नियत होकर इसके बाद फिर 10.8.2016 नियत हुई तत्पश्चात 6.11.2017, 7.11.2017 नियत हुई है। इस प्रकार अपीलान्त को सुनवायी हेतु प्राप्त नोटिस के दिन अधीनस्थ न्यायालय मे कोई तारीख पेशी नियत नहीं थी। उक्त आदेशिका के अनुसार अपीलान्त को सुनवायी का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत दौनायचा एवं बिच्छीदौना के उपभोक्ताओं द्वारा की गयी शिकायते निराधार है क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.2.2016 को की गयी उ.मु.दुकान की जाँच में अपीलान्त द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं किया जाना पाया गया है। तथा शिकायतकर्ताओं के व्यक्तिगत बयान नहीं लेकर सामूहिक बयान लिये गये हैं जिसमे उपभोक्ताओं का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने के कारण विधि विरुद्ध है। अपीलान्त पर कोई गबन आरोप नहीं होने के बावजूद एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्य को नजर अंदाज कर राजनैतिक दबाव में आकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। राशन कार्ड संख्या 93,111,132,98,135,134,96,109,110 के उपभोक्ताओं को राशन कार्ड मे राशन सामग्री का इन्द्राज नहीं होने के आधार पर आरोप लगाया गया है जबकि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 30.6.2016,19.7.2016,5.8.2016 को राशन सामग्री का पीओएस मशीन से वितरण किये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे ऐसी स्थिति में वितरित राशन सामग्री का राशन कार्ड मे इन्द्राज करना कोई मायना नहीं रखती है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.9.2020 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मयाद मय दफा के प्रार्थना के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया है।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार जागृति महिला स्वयं सहायता समूह दौनायचा की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार की जाँच प्रवर्तन अधिकारी से करवायी गयी। दौराने जाँच डीलर द्वारा रसद सामग्री नहीं देना, मौके पर हसन खां ने स्टेट बीपीएल के कार्ड पर 3 माह का गेहूँ नहीं देना पाया गया तथा सामूहिक बयानों मे भी उपभोक्ताओं ने रसद सामग्री का नियमित वितरण नहीं होना बताया। मौके पर राशन कार्ड संख्या 93,111,132,98,135,134,96,109,110 का अवलोकन किया जाने पर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड मे राशन सामग्री नहीं देना पाया जाने पर पत्रांक 2116 दिनांक 26.11.2015 द्वारा अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया व जाँच विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक 221 दिनांक 11.3.2016 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की राशन सामग्री की आपूर्ति चालू कर दी गयी। अन्य अभियोग संख्या 87/2017 मे प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूंगर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की जाँच करने पर रसद सामग्री उपलब्ध होने पर भी पीओएस मशीन में शुन्य ट्रान्जेक्शन किया है जिसके कारण उपभोक्ता खादय सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित रह जाने पर आदेश क्रमांक 3782-91 दिनांक 31.10.2017 द्वारा निलम्बित कर पत्रांक 3827-28 दिनांक 31.10.2017 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवायी 15.11.2017 थी किन्तु उक्त दिनांक को अपीलान्त द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके पश्चात अपीलान्त को कई नोटिस जारी किये गये किन्तु उनका जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,9, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/- रु सम्पहरण करते हुए अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

.....(2).....


  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

(अपील संख्या 58/2020)

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उचित मूल्य दुकानदार जागृति महिला स्वयं सहायता समूह दौनायचा की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार की जाँच प्रवर्तन अधिकारी से करवायी गयी। दौराने जाँच डीलर द्वारा रसद सामग्री नहीं देना, मौके पर हसन खां ने स्टेट बीपीएल के कार्ड पर 3 माह का गेहूँ नहीं देना पाया गया तथा सामूहिक बयानों में भी उपभोक्ताओं ने रसद सामग्री का नियमित वितरण नहीं होना बताया। मौके पर राशन कार्ड संख्या में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड में राशन सामग्री नहीं देना पाया जाने पर पत्रांक 2116 दिनांक 26.11.2015 द्वारा अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया व जाँच विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक 221 दिनांक 11.3.2016 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की राशन सामग्री की आपूर्ति चालू कर दी गयी। अन्य अभियोग संख्या 87/2017 में प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूंगर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की जाँच करने पर रसद सामग्री उपलब्ध होने पर भी पीओएस मशीन में शून्य ट्रान्जेक्शन किया है जिसके कारण उपभोक्ता खादय सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित रह जाने पर आदेश क्रमांक 3782-91 दिनांक 31.10.2017 द्वारा निलम्बित कर पत्रांक 3827-28 दिनांक 31.10.2017 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवायी 15.11.2017 थी किन्तु उक्त दिनांक को अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्ट की सुनवायी हेतु जारी नोटिस क्रमशः दिनांक 21.9.2016, 21.4.17, 31.5.17, 28.6.2017, 14.7.2017, 22.8.2017, 12.9.2017, 20.9.2017, 30.10.2017 में से दिनांक 22.8.17 के नोटिस की तामील अपीलान्ट को हुई थी जिसमें आगामी तारीख 7.9.2017 नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में तारीख पेशी 10.5.2016 से 27.5.2017 नियत होकर इसके बाद फिर 10.8.2016 नियत हुई तत्पश्चात 6.11.2017, 7.11.2017 नियत हुई है अर्थात् न्यायालय में 7.9.2017 की तारीख पेशी नियत ही नहीं थी। इसी प्रकार दिनांक 31.10.2017 के नाटिस में सुनवायी की तारीख 15.11.2017 नियत की गयी थी किन्तु मुताबिक आदेशिका उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में कोई तारीख नियत नहीं थी। इसके अलावा उपभोक्ताओं के सामूहिक बयानों के आधार पर अपीलान्ट को दोषी पाया गया है जबकि सभी उपभोक्ताओं के पृथक-पृथक बयान लिये जाने चाहिए थे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए सामूहिक बयान वाले उपभोक्ताओं को तलब कर उनके बयानों को रिकार्ड पर लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे तथा निर्णय दिनांक तक उक्त अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त ही रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.2.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र किशन)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर